

एयर इंडिया क्रैश- टेकऑफ से पहले ही बंद कर दिए गए फ्यूल स्विच? अमेरिका की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

स्वतंत्र प्रभाव

अहमदाबाद- 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया को पलायन AT-171 की दुर्घटना ने देश ही नहीं, दुनिया को भी झकझोर दिया। इस हादसे में 270 लोगों की मौत हुई, जिसमें 241 यात्री और 29 जमीनी लोग शामिल थे। अब इस भीषण विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भारत में किसी भी वक्त जारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले अमेरिका को एक बड़ी मीडिया रिपोर्ट ने मामले में नया मोड़ ला दिया है।

क्या टेकऑफ़ से पहले ही बंद कर दिए गए थे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम?

‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ (WSJ) की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि फ्लेन के दोनों इंजनों में फ्यूल कंट्रोल सिस्टम टेकऑफ़ के समय बंद कर दिए गए थे। यही वजह बताते जा रहे हैं कि विमान ने रनवे छोड़ने के कुछ ही सेकंड बाद श्रद्धा खो दी और नीचे की ओर गिरने लगा। विमान अंततः एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया।

कोई तकनीकी खराबी नहीं, फोकस इंसानी गलती पर



अब तक की जांच में बोईंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों में किसी किस्म की यांत्रिक खराबी के कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। इसके चलते जांच का फोकस और पायलटों के निर्णयों, उनके कॉकपिट मूवमेंट्स और खासतौर पर प्रभूल कंट्रोल स्विच के संचालन पर केंद्रित है। इन स्विचों का प्रयोग सामान्यतः इंजन स्टार्ट/शटडाउन या किसी इमर्जेंसी में किया जाता है, लेकिन टेकऑफ़ के वक़्त इन्का बंद होना बेहद असामान्य और जानलेवा हो सकता है।

ब्लैक बॉक्स की भूमिका होगी निर्णायक

हादसे के कारणों का अंतिम निर्धारण अभी ब्लैक बॉक्स डेटा और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर की जांच पर निर्भर करेगा। फिलहाल शुरुआती जांच में यह संदेह सामने आया है कि संभवतः मानवीय भूल (Human Error) के चलते स्विच बंद हुए हों, लेकिन इस पर

**शुक्रवार रात को निकलेगी जिंदा,
बाबा ने मृत महिला को गोबर में
दफनाकर किया तंत्र-मंत्र**

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से अंधविश्वास से जुड़ा एक हौरान करने वाला मामला सामने आया है। तम्बौर थाना क्षेत्र के चकपुरवा गांव में सर्वदश से 60 वर्षीय महिला की मौत के बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार करने की बजाय, एक बाबा की सलाह पर उसे गोबर से भरे गुट्टों में दफन कर दिया। घटना के अनुसार, कला वीम मां की महिला को शुक्रवार को घर में कटाई हटाने समय सपने ने काट लिया। परिजन उस तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि, डॉक्टरों पुष्टि के बावजूद परिजनों ने 'हद नहीं' मानते और एक स्थानीय कथित बाबा कृपाल दास से संपर्क किया।

गोबर से भरे गड्डे में दफनाने से वह फिर से जीवित हो सकती है!

बाबा ने दावा किया कि महिला को गोबर से भरे गड्डे में दफनाने और तब-तब करीब से वह फिर से जीवित हो सकती है। इसके बाद रात 8 बजे महिला को उसी गड्डे में दफनाया गया। बाबा ने कहा है कि शुक्रवार रात फिर से खुदाई की जाएगी और यदि "ऊपरवाले की मर्जी" हुई, तो महिला जिदा वापस आ सकती है। गाँव में अब इस पूरी मामले को लेकर चर्चा का माहौल है, जबकि प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह घटना एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में फैले अधर्यासवाद और अज्ञानता की कमी से तस्वीर पकट रही है।

**पंजाब-हरियाणा के कई ठिकानों पर
E D की छापेमारी, मचा हड़कंप**



पंजाब-हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, यहां ई.डी. (इन्फोर्मेशन डायरेक्टोरेट) ने शुक्रवार को दोनों राज्यों के कई इलाकों में रेड की, जिससे हथ्थ तरफ भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि उक्त छापेमारी इस साल अमेरिका द्वारा डिमांड किए गए अवैध भारतीय प्रवासियों से जुड़े 'ऊंची रेड' मामले की मनी लॉन्ड्रिंग जॉकों के सिलसिले में की जा रही है। इनमें अमृतसर, संगरूर, पटियाला, मोगा समेत दोनों राज्यों के कई शहर शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, पंजाब के मानस और हरियाणा के कुरुक्षेत्र व करनाल में कुल 7 स्थानों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत तलाशी अभियान चलाया गया। यह छापेमारी 9 जुलाई को दोनों राज्यों में की गई कार्रवाई में मिले सुरागों के आधार पर की गई। ईडी ने बताया कि 9 जुलाई को की गई छापेमारी के दौरान 30 असली पासपोर्ट बमरद किए गए थे। साथ ही, उन एजेंटों और इमीग्रेशन एजेंसियों की पहचान भी हुई है जो भारतीयों को 'ऊंची रेड' के जरिए अमेरिका जैसे देशों में गैर-कानूनी रूप से भेजने का कारोबार चला रहे थे।

अंतिम निष्कर्ष जांच ब्यूरो ही निकालेगा।
**भारत में भी जांच लगभग पूरी,
 रिपोर्ट किसी भी वक़्त**
 भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट
 इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने पहले ही
 संकेत दिए थे कि हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट
 11 जुलाई के आसपास सार्वजनिक की जा
 सकती है। ICAO (International Civil
 Aviation Organization) के नियमानुसार,
 किसी भी विमान दुर्घटना के 30 दिन के भीतर
 सदस्य देशों को शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी
 करनी होती है। भारत ICAO का सदस्य है,
 और इसी दिशा में यह रिपोर्ट तैयार की जा
 रही है।

**एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति की
गवाही भी अहम**

इस भीषण हादसे में चमत्कारिक रूप से एक यात्री जीवित बच गया, जिसने बाद में बताया कि टेकऑफ़ के कुछ ही क्षणों में

विमान के अंदर कंपन और झटका महसूस हुआ था, और फिर अचानक सब अंधेरा हो गया। उसकी गवाही और कॉकपिट डेटा दोनों को जांच का हिस्सा बनाया गया है।

क्या कहती है बाले स्ट्रीट जर्नेल की रिपोर्ट?

WSJ ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि शुरूआती निष्कर्षों के अनुसार दुर्घटना के पीछे खराब बड़ कारण दोनों इंजनों में ईंधन प्रवाह को नियंत्रित करने वाले स्विचों का बंद होना हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, जांचकर्ता अब इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्विच बंद कैसे और क्यों हुए—क्योंकि ऐसा कदम जानबूझकर नहीं, तो गलती से ही लिया गया होगा।

नजरोँ अब्ब भारत की रिपोर्ट पर
अब सारी निगाहें भारत की ओर से जारी होने वाली प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो हादसे के संभावित कारणों की आधिकारिक झलक देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की विस्तृत तकनीकी जांच की दिशा यह कि जाएगी और संभावित सुरक्षा सुधारों की सिफारिशें भी सामने आ सकती हैं।

कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने न्याय व्यवस्था पर उठाए सवाल कहा इंसान अभी अधूरा



स्वतंत्र प्रभात

टेलर कन्हैयालाल की हत्या पर बनी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद पीड़ित परिवार की पीड़ा फिर से उभर आई है। कन्हैयालाल के बेटे यश तेजी ने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, 'फिल्म पर तुरंत सुनवाई हो जाती है, लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी मेरे पिता के हत्यारों को सजा नहीं मिली। आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा?' 'उदयपुर फाइल्स', जो 11 जुलाई को देशभर के लगभग 3500 सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, अब हाईकोर्ट के आदेश के चलते फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इसमें उदयपुर के भी तीन प्रमुख थिएटर शामिल थे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह अपनी आपत्ति केंद्र सरकार के पास दर्ज कराएं और सरकार को सात दिन में सिनेमैटोग्राफ अनियंत्रण की धारा 6 के तहत निर्णय देने को कहा है।

गौरतलब है कि यह फिल्म 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की उनकी दुकान में निमग्न हत्या पर आधारित है। यह हत्या मोहम्मद रिशाय और गैस मोहम्मद ने दिव्दहाड़े अजमा दी थी। मामले को जांच एआईए द्वारा का जा रही है, और अब तक 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। हालांकि, दो आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बालू और मोहम्मद जावेद - को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जिससे पीड़ित परिवार खुद को असह्य महसूस कर रहा है। यश तेजी का कहना है कि '1 केवल हमारे परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देश को न्याय व्यवस्था का सवाल है। अगर फिल्म की रिलीज को रोकना जा सकता है, तो क्या हमारे लिए ईसाफ भी नहीं मिल सकता?' कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर देशभर में भावनात्मक माहौल रहा है, और अब फिल्म पर रोक से एक नई बहस छिड़ गई है। क्या हमारी आदालतें संवेदनशील हैं? मामले में न्याय की प्राथमिकता तय करने में संतुलन बना पा रही है?

मां-बेटी व आशिक... पहले शराब पिलाई, लहलुहान करने के बाद साथ मिलकर देखी फिल्म और फिर कैब में...

स्वतंत्र प्रभाव

प्यार और मोह के झांसे में आकर आजकल लोग पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। तेलंगाना एक ऐसा गजब लोकिन भयानक मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे 'थै इंसान हैं या हैवान' ! यहाँ प्यार के चक्कर में एक माँ, बेटी और उसके प्रेमी ने मिलकर एक धिनैने अपराध को अंजाम दिया। इन तीनों ने मिलकर पहले अपने पिता को शराब पिलाने के बाद जमकर पीटा फिर उसकी हत्या कर दी।

अवैध संबंध बना हत्या की वजह

दरअसल यह मामला तेलंगाना के घाटकेसर का है। 45 साल के वल्लूरी लिंगम एक अपार्टमेंट में बॉवैमन के रूप में काम करते थे। उनकी पत्नी शारदा जोएचएमसी में स्वीपर थी और उनकी 25 साल की बेटी मनीषा का विवाह हो चुका था लेकिन वह अपने पति से अलग रह रही थी। शारी के बाद मनीषा का जावेद नाम के एक युवक के साथ अवैध संबंध था। लिंगम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अक्सर बेटी को जावेद से दूरी बनाने को कहते थे।

माँ, बेटी और प्रेमी ने मिलकर रची साजिश

मनीषा अपने प्रेमी जावेद के साथ मॉलाली में किराए के मकान में रह रही थी। इस बात को लेकर मनीषा और लिंगम का अक्सर झगड़ा होता रहता था। दूसरी ओर लिंगम की पत्नी शारदा ने भी मनीषा को बताया कि उसका पति उस पर भी शक करता है और उसे परेशान करता है। यहीं से मां, बेटी और प्रेमी की खौफनाक प्लानिंग शुरू हुई।

हत्या के बाद बेफिक्र होकर फिल्म्स देखने गए तीनों

5 जुलाई को शारदा ने लिंगम को लड्डू में नींद की गोलीयां मिलाकर दीं जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद 6 जुलाई को जावेद को बुलाया गया। तीनों ने मिलकर पहले लिंगम को शराब पिलाई फिर जमकौरा पेटा। इसके बाद जावेद ने रस्सी से गला घोटकर लिंगम की हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों ने शव को चादर में लपेटकर रख दिया और बेफिक्र

अब मध्यप्रदेश से निकलेंगे माल्या और नीरव? SBI के अफसरों ने ऐसा कांड कर दिया, जो कोई सोच भी नहीं सकता...

मध्य प्रदेश के विदिशा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में करोड़ों के लोन घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ब्रांच अधिकारियों ने बिना अधिकार बाटे लोगों को लोन दे दिया और करोड़ों रुपए लेने के बाद उधारकर्ता गायब हैं। गड़बड़ घोटाले का ये बड़ा खेल 2023 से शुरू हुआ। जहां बिना किसी अधिकृत पावर के लोन बाटे गए। एक 20 से अधिक उधारकर्ता लापता पाए गए हैं। विदिशा की एसबीआई शाखा में हुए करोड़ों के घोटाले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब ब्रांच के पास लोन स्वीकृत करने की शक्ति ही नहीं थी, तो इतनी बड़ी रकम किसके इशारे पर और कैसे स्वीकृत हुई?

कागजों में लोन, जमीन पर लूट!

मामले में सबसे बड़ी लापरवाही यह पाई गई कि बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिना फील्ड विजिट, बिना किसी क्रेडिट असेसमेंट के फाइलें मंजूर की गईं। ना आवेदकों की सही पहचान की गई, ना उनके बिजनेस का जाजूद, फिर भी करोड़ों की राशि सीधे खातों में ट्रांसफर कर दी गई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सुनियोजित बैंक छेड़नी है या अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गई है।

भोपाल से चला रिमोट- विदिशा में लिखी स्क्रिप्ट?

इस पूरे प्रकरण में भोपाल के सीनियर अफसरों की भूमिका अब शक के घेरे में है। विशेष रूप से तत्कालीन G M एवं वर्तमान

नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म और सहयोग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार



वहां आरोपी रहेहन ने परिवारिया की नाबालिग बेटी के साथ कार में ही दुष्कर्म करेका। इस दौरान शम्मी और रिजवान ने मिलकर इस पूरी घटना को वीडियो भी बनाया। दुष्कर्म के बाद, आरोपियों ने लड़की को सड़क पर पटक दिया और यह धमकी देते हुए चले गए कि यदि उसने इस घटना को बारे में किसी को बताया तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे, साथ ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। रिपोर्ट पर तुरंत मामला दर्ज कर अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस राजीव कर सह वृत्तधिकाारी वृत्त नवलगढ़ अणुधर सिंह द्वारा आरंभ किया गया। प्रकरण में घटना की गंभीरता को देखते हुए, साक्ष्य संकलित कर नामजद आरोपियों रहेहन पुत्र

दिखावें दो। पुलिस की दिशा के बाद नामजद आरोपी रहान, शम्मी और रिजवान को दस्तक्याब कर लिया गया। अनुसंधान के बावजूद अरुण खिलफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त वाहन अटिंगा को भी जब्त कर लिया गया है। इस सफल अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सह वृताधिकारी राजनोय सिंह चम्पावत के नेतृत्व में थाना प्रभारी हेड कांस्टेबल रामप्रताप और हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, सुन्दर कर्खा, कांस्टेबल मुल्तानागाम, बाबूलाल और प्रमोद कुमार शामिल रहे। कांस्टेबल मुल्तानागाम और बाबूलाल ने आसुफा संकलन में विशेष भूमिका निभाई।

इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी की खौफनाक हत्या

●बेटी बनाती थी Reels,
समाज के चक्कर में पिता ने
बरसाईं ताबड़तोड़ 5 गोलियां

स्वतंत्र प्रभाव

हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर-57 इलाके से गुरुग्राम को एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। इंटरनेशनल टैनिस् खिलाड़ी राधिका यादव को उसके ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। वादरात को सुबह 10:30 बजे के करीब अंजाम दिया गया। राधिका उस वक्त अपने घर की पहली मंजिल पर स्थित किचन में काम कर रही थी।

आरोपी पिता की पहली तस्वीर आई सामने

अब इस हत्याकांड ने नया मोड़ लिया है। इस ससन्तनीखेज वादरात के आरोपी पिता दीपक यादव को पहली तस्वीर सामने आई है। जोकि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में दीपक पुलिस हिरासत में आंखें झुकाए और चेहरे पर शिक्कन लिए खड़ा नजर आ रहा है। आरोपी पिता की तस्वीर देख लोगों में काफी गुस्सा है। लोग सोशल मीडिया पर न्याय की मांग कर रहे हैं।

**राधिका को मारी गईं थीं पांच
गोलियां**

पुलिस के अनुसार, गुरुवार सुबह दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका को लाइसेंस रिवांल्वर से पांच गोलियां मारीं। इनमें से तीन गोलियां राधिका की पीठ में लगीं, जिससे उसकी मौत केर पर ही मौत हो गई। हत्या का कारण लोकप्रिय द्रष्टा संचालित टेनिस अकादमी को राधिका पिता-पुत्री के बीच चला आ रहा विवाद बताया जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि दीपक यादव को समाज में यह कहा जाना बुरा लगता था कि वह अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर हैं। साथ ही दीपक यादव को बेटी का रील बनाना भी पसंद नहीं था। इसी मानसिक तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया।

उसके खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 56 थाने में हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि राधिका की सोशल मीडिया गतिविधियों, निजी संबंधों या अकादमी से जुड़े विवाद में कोई अन्य कारण या व्यक्ति शामिल था या नहीं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थीं राधिका

राधिका यादव भारत की एक प्रतिभाशाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी थीं। उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और उनमें जीत भी दर्ज की। उनकी इस तरह से हुई दुःखद मृत्यु से खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर खलेपनी, आमजन और तमाम जाने-माने चेहरे उनकी हत्या को लेकर दुःख और गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं।

भारत को जनसंख्या का तिलस्म भेदना होगा

अवरोध नहीं उत्पादक बने
जनसंख्या।

भारत एक दशक के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा और सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला भी देश होगा, अब समय आ गया है जब देश की सरकार और समूचे जनसंख्या प्रधान की इकाइयों को सक्रिय होकर बढ़ती जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों के बीच सामायिक संतुलन बनाकर बड़ी जनसंख्या को बोझ न मानकर एक शक्ति के रूप में स्थापित कर के इसका सर्वाधिक दोहन राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए नहिह करे। निचता तौर पर यह हम पर है कि हमारी युवा जनसंख्या का उपयोग हम सही तरीके से विकास की गति के साथ साथ तालमेल बिठकर इसे राष्ट्र के विकास के श्रोत की तब तक सिसत करे घ भारत की युवा और दिवा शक्ति के माध्यम से साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, सेना, कंप्यूटर साइंस और स्वयं उद्यम के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भारत को अग्रणी देश बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए छ अब इस विशाल जनसंख्या का सीमित संसाधन पर कितना दबाव होगा, आप ये कल्पना कर सकते हैं। बहुत अधिक जनसंख्या देश में अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक समस्याओं को जन्म भी देती है। वर्तमान में भारत 141 करोड़ जनसंख्या (अनुमानित) के साथ विश्व में दूसरे नंबर पर है पहले नंबर पर चीन (145 अनुमानित) करोड़ की आबादी वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1989 से 11 जुलाई को हर वर्ष जनसंख्या दिवस के रूप में मनाता है पर जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या नियोजन पर भारत जैसे देश में कोई भी योजना नहीं बनती है। यही जनसंख्या बढ़ चुकी है और भारत में युवा जनसंख्या 55% से ज्यादा है तो इसका सुकारोत्मक उपयोग ही किया जाना युक्ति युक्त होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत की जनसंख्या बाजार की ताकत है पर

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जनसंख्या विकास के लिए बड़ी बाधक भी है। अधिक जनसंख्या के दबाव में सीमित संसाधन छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। आम जनता को उनकी मूल जरूरतों की आवश्यक वस्तुएँ नहीं मिल पाती और यही मिलती भी है तो बहुत उंची दरों में या बहुत महंगाई के बाद। ऐसे में देश में अनेक समस्याएँ पैदा होती हैं, और सबसे ज्यादा जनसंख्या के दबाव से विकास के ज़्यादा संकेत खड़ो हो जाता है। विकास धीरे-धीरे मध्यम का अवरोद्ध हो जाता है। देश का आर्थिक नियोजन चरमराने लगता है। वर्ष 1951 से 81 के दशक को भारत की जनसंख्या की विफोर्टक अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर के तीव्र स्खलन और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ है। वर्ष 1921 तक की अवधि में भारत की जनसंख्या की वृद्धि स्थिर अवस्था में रही क्योंकि इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी निम्न थी। 1981 से लगातार अभी तक जनसंख्या की दर बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बढ़ती जनसंख्या के मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस परियोजना परियोजना मानव का अधिकार' रखा गया है, ताकि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं के प्रति जागरूक होकर लोगों द्वारा परिवार नियोजन पर उत्साहजनक जोर दिया जाए। यह स्लोलाय यह संकेत करता है कि सुसुधित एवं शैक्षिक परिवार नियोजन एक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है और यह सभी लोगों को सशक्त बनाएगा और देश विकास की गति को तेज करे में सहायक भी होगा। भारत की जनसंख्या बढ़ने का प्रमुख कारण बढ़ती जन्म दर और कम मृत्यु दर भी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में बेरोजगारी गरीबी पर्यावरण प्रदूषण जैसे समस्याएँ चुनौती बनकर सामने आईं जो समाज व्यक्ति और राष्ट्र सभी के विकास

को अवरुद्ध करती है। हमारे पास उपलब्ध संसाधन इतनी बड़ी आबादी के लिए कम पर्याप्त नहीं है। विकास और देश की समृद्धि के लिए जनसंख्या नियंत्रण एक आवश्यकता अहो हो सकता है। कई यूरोपीय देशों ने अपनी बढ़ती जनसंख्या एवं संसाधनों में उच्चतम तात्प्रेल हेतु परिवार नियंत्रण प्रणाली को का निर्णय लिया किंतु एक समय बाद वहां कार्यशील जनसंख्या की अपेक्षा वृद्धों की संख्या में वृद्धि हुई जिससे मानव संसाधन की समर्याएँ उनके सामने नए लगी हैं। चीन में पहले जनसंख्या नियंत्रण किया गया था। सरकार ने वैधानिक रूप से एक या दो बच्चे पैदा करने की शर्तें लागू की थी, पर बाद बुजुर्गों, वृद्धों की संख्या में भारी वृद्धि होने के पश्चात चीन की सरकार ने ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपनी जनता से अपील की है। जापान एक छोटा सा देश होने के बावजूद अपने सीमित संसाधनों के चलते अपने नवाचार तथा तकनीकी शक्ति के बल पर विकासशील देशों के समकक्ष खड़ा है।

भारत जैसे विशाल देश में जहाँ बहु-
बड़ी जनसंख्या भी है और विकास के लिए
आवश्यक संसाधन भी हैं, विकास करने के
लिए केवल विशाल संसाधनों के साथ
सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता होगी।
भारत में जनसंख्या निबंधन के साथ-साथ
उसके अनुपात में संसाधनों का संतुलन बनाना
कर विकास की नई दिशा दी जा सकती है।
संसाधनों की उचित दोहन हो रही और
सटीक नीति तथा उसके क्रियान्वयन की
आवश्यकता होगी। इसके अलावा नवाचार
एवं उचित तकनीक प्रौद्योगिकी का
अमल में लाना होगा। भारत विश्व का प्रथम
देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन
कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया। इसका
परिणाम भी अच्छा हुआ था कि पिछले कुछ
दशकों में जनसंख्या की वृद्धि
संतोषजनक गिरावट आई है। यह तो विदित
है कि किसी भी राष्ट्र की संतुलित विकास

की धारा तभी संभव है जब वहाँ के विकास में सहायक संसाधनों का संतुलन बना रहे किसी एक घटक का संतुलन यदि गड़बड़ होता है तो विकास के लिए गंभीर समस्याएँ जन्म लेना शुरू करती हैं। भारत की जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो दिन-दूर नहीं जब संसाधनों की कमी से भारत को जूझना होगा फिर विकास की बात बेमानी हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जनसंख्या विकास मानने का उद्देश्य है कि व्यक्ति समान दरकार और योजना कानूनों के मन में इस विषय से संबंधित समस्याओं के प्रति चेतन संवेदना जानना ही है ताकि लोगों में बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी समस्याएँ एवं अवरोधों के बारे में जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित हो। भारत के पास विकास के सभी मापदंड होते हुए भी देश पिछड़ा हुआ है, भारत में तकनीकी का कम विकास कमजोर शिक्षा, परंपरागत स्रोत, कृषि का निम्न स्तर, आर्थिक असमानता जैसे अनेक समस्याएँ हैं जो विकास में बाधक बनती रही हैं। वर्तमान में देश के पास प्राकृतिक एवं मानव संसाधन इतना है कि बढ़ती जनसंख्या की समस्याओं से आसानी से निपटा जा सके पर इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि संसाधनों का उचित दिशा तथा उसका सही उपयोग विकास को दोहन में प्रश्नचर से बचाकर किया जाए यह अत्यंत उल्लेखनीय है कि जनसंख्या की समस्या से निपटने तथा विकास की दृष्टि को बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल शासन प्रशासन की ही नहीं है इसके लिए आम जन नागरिक भी जिम्मेदार हैं क्योंकि समस्याएँ खड़ी करने में आमजन का एक बड़ा वजन भी है, इसीलिए हम सबको जनसंख्या नियंत्रण और विकास की धारा को सहज दिशा प्रदान करने के लिए सक्रिय सहयोग देना होगा तब ही देश एक सशक्त राष्ट्र बन पाएगा।

संजीव ठाकर

बिहार में महिला आरक्षण

बिहार में आगामी नवम्बर-दिसम्बर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसे देखते हुए सत्ता और विपक्ष के दल अपनी-अपनी राजनैतिक चौसर बिछाने लगे हैं। ताजा फैसले में राज्य की भाजपा-जद(यू) नीतीश सरकार ने सरकार नैकरियों में महिलाओं के 35 प्रतिशत अंशकालीन को राज्य की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए आवश्यक करार दिया है। इससे पहले अन्य राज्यों की महिलाओं के लिए भी नौकरियों के द्वा़र खुले हुए थे। मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार महिला वयं लोकप्रिय समझे जाते हैं। इसकी कई वजहें समझी जाती हैं। पहली तो यह कि उन्होंने राज्य में पूर्ण शराबबन्दी करके घरेलू महिलाओं को राहत देने की कोशिश की थी। मुख्यमन्त्री का यह फैसला राज्य की महिलाओं ने बहुत सराहा था। इससे उष्का पारिवारिक जीवन सुगम होने की संभावना बढ़ी थी। शराबबन्दी से गरिब तबक की महिलाओं में खुशी की लहर थी मार दूसरा पहलू यह भी है कि इससे राज्य में अवैध तरीके से शराब तस्करी भी बढ़ी और राज्य में जहरीले शराब पीकर मरने वाली संख्या में भी इज़फ़ा हुआ। नीतीश सरकार ने इस समस्या का हल पुलिस प्रशासन की मार्फ़त ढ़ूंढने की कोशिश की जिसमें उसे आंशिक सफलता भी मिल पाई। यह भी सच है कि अवैध शराब की तस्करी करने वाले को हार में और प्रशासन इसमें तस्करी अब भी हो रहती है। इससे भी तस्करी बन्द करने में सफल नहीं हो सका है। किसी भी समाज में

एसी बुराई को जड़ से समाप्त करना बहुमुखित्व काम माना जाता है। फिर भी राज्य की महिलाओं ने मुख्यमंत्री की शराबबन्दी की घोषणा का खुले दिल से स्वागत किया था जहां तक महिलाओं के सरकारी नौकरियों के आरक्षण का सवाल है तो मुख्यमंत्री ने यह फैसला 2016 में किया था। उस समय नीतीश बाबू जद(यू)-कांग्रेस व लालू जी की पाटी राजद के महागठबंधन की सरकार के मुखिय थे। इससे पहले 2015 को हुए राज्य विधानसभा चुनावों में इस गठबंधन को भाजपा के मुकाबले भारी सफलता मिली थी। आज चुनावों में राज्य की महिलाओं ने नीतीश बाबू का साथ दिया था। तभी से महिला वोट बैंक नीतीश बाबू का समझा जाता है। पिछले 20 साल से 2005 के बाद से नीतीश बाबू ही राज्य के मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं हालांकि राज्य में सतारूढ़ सरकार के गठबंधन अदलते-बदलते रहते हैं। नीतीश बाबू की भाजपा के साथ मिलकर सत्ता में रहते हैं तो कभी कांग्रेस व लालू जी की पार्टी के साथ अतः पिछले 20 सालों में बिहार सरकार ने जो भी फैसले जर्जित किए हैं उन सभी का श्रेय नीतीश बाबू को दिया जा सकता है। 2022 में उन्होंने बिहार में जातिगत संवर्धन कराया था उस समय नीतीश बाबू लालू जी की पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने हुए थे। इस संवर्धन का श्रेय हालांकि लालू जी की पार्टी ने लेने का प्रयास किया मगर नीतीश बाबू ने स्पष्ट कर दिया कि बिना नीतीश बाबू के बिना लालू जी की पार्टी का कोई भी फैसला नहीं हो पाता।



यिा किा इा स फैसलै में उनकी भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके पास राज्य के अति पिछड़े वर्ग का व्यापक समर्थन है। इस जातिगत सर्वेक्षण से साफ हुआ कि बिहार में 36 प्रतिशत लोग अति पिछड़े वर्ग के हैं। जातिगत संवेदनशीलता बाद नीतीश सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों की मदद के लिए कुछ जरूरी कदम भी उठाये और अति गरीब परिवारों को दो लाख रुपये की मदद देने का फैसला भी किया। इस प्रकाशन के बाद नीतीश ब्रह्म इस की सहानुभूति बटोरने में पुनः सफल रहे। जहां तब कि व्षिक का सवाल है तो वह चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कराये जाने के खिलाफ व्यापक अभियान चलाये हुए हैं और इस सन्दर्भ में उनसे बुधवार को बिहार बन्द का आयोजन भी किया गया। इस बन्द के सफल होने की खबरें भी आ रही हैं जिससे इस चुनौती वाली राज्य में जनता बनाम चुनाव आयोग की स्थिति पैदा होती जा रही है लेकिन नीतीश और इस विवाद से तटस्थ नहीं हुए हैं और वह मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर अपनी जमानत नहीं खोले

रहे हैं। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री इस घटना के राजनीतिक हानि-लाभ के समीकरणों को तोल रहे हैं और सही समय पर अपनी बात कहने के इंतज़ार में हैं। लेकिन इस विवाद से लोगों खासकर महिलाओं का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरियों में स्थायी निवास वाली महिलाओं का मुद्दा गरमा दिया है। जाहिर तौर पर इससे नीतीश बाबू का महिला वोट बैंक सशक्त होगा। अभी तक यह व्यवस्था थी कि 35 प्रतिशत महिला आरक्षण में किसी भी राज्य की महिलाएँ बिहार में नौकरी पा सकती थीं। नौकरियों के क्षेत्र में अल्पांक की नौकरियों में बिहार से बाहर की महिलाओं को भी अच्छी-खासी संख्या में नौकरियाँ मिली थीं। अब ये सब नौकरियों केवल बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित हो जायेंगी। इससे राज्य का राजनीति में जिस प्रकार जातिवाद को बोलबाला है वह भी कम होगा क्योंकि आरक्षण में हर जाति की महिला पात्र मानी जायेगी। इससे भाजपा को चुनावी मैदान में उतरने में मदद मिलेगी क्योंकि यह पार्टी मूल रूप से आरक्षित समाज की पार्टी समझी जाती है। जद(यू) के साथ मिश्रकल ही भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव लड़े थे जिसमें उसे शानदार सफलता मिली थी। अतः विधानसभा चुनावों की चौसर में सत्ता व विपक्ष अचानक-अचानक गोटियाँ बहुत सावधानी के साथ बिछाने जरूर आगे रहें।

सिखों के दो तख्तों में टकराव के लिए जिम्मेवार कौन?

इतिहास में पहली बार सिखों के दो तख्तों में
 टकराव देखने को मिल रहा है जिसे समाप्त करना
 अति आवश्यक है अन्यथा आने वाले दिनों में
 इसके अंगीयर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
 युवा वर्ग इस सबके चलते ही आज सिखी से
 हटा चला जा रहा है मगर अफसोस कि इस ओर
 कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। सिख समाज में
 ज्येष्ठद्वारों का विशेष तौर पर दायित्व बनता है कि
 वह कौम के भीतर आए विवाद को समाप्त करके
 सभी सिखों को एकजुट होकर एक निराले
 साहिब के भीतर लाएं मगर आज तो ज्येष्ठद्वार
 स्वयं विवाद के घेरे में आ चुके हैं अब इनमें
 एकजुटता कैसे और कौन लेकर आएगा यह
 अपने आप में प्रश्न बन गया है। तख्त में विवाद
 तब खड़ा हुआ जब श्री अयाल सहज साहिब से
 ज्ञानी कुलदीप सिंह गढ़वाल के द्वारा तख्त पटना
 साहिब से तनखैया और पंथ से निष्कासित पूर्ण
 ज्येष्ठद्वार रणजीत सिंह गौहर को नाम करते हुए
 उन्हें पहले की भांति सेवाएँ निभाने हेतु आदेश
 जारी कर दिया इतना ही इसकें साथ ही तख्त
 पटना साहिब के मौजूदा ज्येष्ठद्वार सिंह साहिब
 ज्ञानी बलदेव सिंह और ज्ञानी गुरदयाल को
 सेवाओं पर रोक लगा दी गई। इस पर तख्त पटना
 साहिब के ज्येष्ठद्वार सहित पंथ चारों साहिबाने
 ज्ञानी कुलदीप सिंह गढ़वाल और ज्ञानी टेक
 सिंह को तनखैया पर देह दिए इस पूरे मामले में

सांजिशकर्ता के रूप में मानते हुए सुखबीर सिंह बादल को पेशे होकर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिनों का समय दिया गया। हालांकि चाहिये तो यह था कि सुखबीर सिंह बादल पेशे होकर अपना पक्ष रखते और वह साहब चालते भी मगर उनके कुछ सलाहकार ऐसे हैं जिन्होंने उनसे ऐसा करने से रोका जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। 40 दिनों बाद भी जब सुखबीर सिंह पेशे नहीं हुए तो तख्त पटना साहिब से उन्हें तनखेया कर दिया गया। जिसके बाद माने पंजाब की राजनीति में भूचाल सा आ गया। सुखबीर के खिलाफ आंदेश आते ही जानी कुलद्वी सिंह दागडा तुरन्त हस्तक्षेप में आए और उन्होंने अपना आका को बचाने के लिए उन्होंने तख्त पटना साहिब के दो सदस्यों हरपाल सिंह जैतल और ड. गुरमीत सिंह सहित जानी गुरदयाल सिंह को भी तनखेया कर दिया। इस पर संसार भर से सिख बुद्धिजीवियों द्वारा विन्तन किया जा रहा है और उनका मानना है कि सभी तख्त अपने आप में सम्मानित हैं इसलिए सभी जन्मेदारों को चाहिए कि बड़े छेदों की बात ना करते हुए बिन वजह पंथ में उगे मसले का समाधान निकालें जो लोग स्वयं श्री आकाल तख्त साहिब के आदेशों को दरकिनार करते हुए अपनी राजनीतिक गेटियां सेंकने में लगे हैं आज बहलवाली आकाल तख्त की महानता की दृढ़ाई दे रहे हैं।

इसलिए जय्येदार साहिबान को चाहिए अपनानैतिक फर्ज समझते हुए राजनीतिक लोगों की प्रिफरेंस से बाहर आकर कौम हित में एकजुटता लाने को और अप्रसर हो और जल्द से जल्द इसका स्थायी हल निकाला जाए किसी पक्ष के व्यक्ति विशेष के लिए पूरी कौम को दाव पर लगाना किसी भी सूत्र में सही नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को पढ़ाया जाएगा सिख इतिहास से लेकर कबवा है कि सिख गुरु साहिबान से इतरक बाबा बंदा सिंह बहादुर जैसे अनेक सिख योद्धा हुए जिनका इतिहास आज वच्चे पढ़ लें तो वह सिखों के प्रति हीन भावना रख ही नहीं सकते। इतना ही नहीं अगर विद्यार्थियों ने सिख इतिहास पढ़े होता तो 1984 में सिखों का कत्लेआम भी नहीं होता था और सिखों को खालिस्तानी या आतंकी कहकर भी नहीं पुकारा जाता। दिल्ली यूनिवर्सिटी को पहल पर अब छात्र मुगल राज्य और समाज पर विशेष रूप से तथा सामान्य रूप से भारतीय इतिहास पर अमरते इरेकेशन लेखन में विद्यमान अंतराल को समझ सकेंगे। कोर्स में यूनिट एक के तहत विद्यार्थियों को सिख धर्म का विकास, मुगल राज्य और समाज, पंजाब सिख धर्म में शहादत और शहादती का अवधारणा, सिख गुरुओं की अधीन सिख, गुरु नानक देव जी से गुरु अमर देव जी तक सिख धर्म का ऐतिहासिक संदर्भ पढ़ाया

जाएगा। यूनिट दो में शहादत की गाथा के तहत आधिपत्य मुगल राज्य और दमन, गुरु अर्जुन देव जी, जीवनों और शहादत, राज्य की नीतियों पर प्रतिक्रिया, गुरु हरगोबिंद जी से गुरु हरकृष्ण जी तक, गुरु तेग बहादुर जी के जीवनों और शहादत, भाई मति दास, भाई सती दास, भाई दयाल के संदर्भ पढ़ाए जाएंगे। दिल्ली के यूनिवर्सिटी द्वारा इतिहास में सिख शहादतों और बहादुरी पर अंडरग्रेजुएट में सिख करने के लिए सप्ताह के लोग मोदी की सरकार का सराहनीय काम बताते हुए खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आधार प्रकट करने दिख रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री मनीजन्द सिंह सरिस्सा मानते हैं कि इससे ही सरकारों के बीच का पता चलता है एक और अजगदीर के बाद से कांग्रेस की सरकार ने देशवासियों पर जुल्म करने वाले अत्याचारियों का इतिहास स्फूर्ती कालेजों में बच्चों को पढ़ाया गया अत्याचार की उस आग को ठण्ड कर देश और धर्म की रक्षा वाले गुरु साहिबान और सिख योद्धाओं के इतिहास से वंचित रखा। तख्त पटना साहिब कमेटी के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही, दिल्ली सिख युद्धरा प्रबन्धक कमेटी अध्यक्ष हरमोत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलो प्रतिष्ठा और सिखों के सरकार के इस कदम को प्रशंसा करते दिख रहे हैं।

संपादकीय

क्या लोकसभा रिजल्ट दोहरा पायेगी सपा

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आइए जानें कि विभिन्न पार्टियों की रणनीति और संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली सफलता उस्ताहित हैं और इस सफलता के द्वापरा वो 27 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दम भर रहे हैं। लेकिन क्या लोकसभा वाली सफलता सभा विधानसभा में दोहरा पायेगी इस पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में सपा को पराजय का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में जिस अयोध्या की सीट पर मिली जीत पर अखिलेश यादव इतना रहे थे उसी की विधानसभा सीट मिली।पुर उप चुनाव में वो हार चुके हैं अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जो सफलता प्राप्त की थी उसमें दलित का एक बड़ा वर्ग उनके साथ गया था और इसीलिए अखिलेश यादव ने आम की राजनीति के लिए पीडीए का नाम दिया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। इसी संयोजन से अखिलेश 27 का राण जीतने की तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह पीडीए सम्मेलन किये जा रहे हैं, पीडीए को जोड़ा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुजन समाज पार्टी की नींव अब उत्तर प्रदेश में खिसक चुकी है। यदि वर्तमान स्थिति को देखें तो लोकसभा में उसका एक भी सांसद नहीं है जब कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में मात्र उनका एक सांसद है। लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी के कमजोर होने का लाभ समाजवादी पार्टी को मिला था। अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी दलित उनका उतना ही साथ दे तो वो बहुमत के करीब पहुंच सकेंगे। लेकिन यहां किनारी



है वह विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिली है। विधानसभा उपचुनाव 9 सीटों पर हुए थे जिसमें भाजपा गठबंधन की को 7 सीटों पर जब कि समाजवादी पार्टी को मात्र 2 सीटों पर विजय मिली थी। यही नहीं सपा अयोग्य की मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी हार गई थी। अयोग्य के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे मिल्कीपुर से उप चुनाव लड़े थे। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा पीडीएम को लेकर तैयारियां कर रही है तो भाजपा जनता पार्टी की रणनीति भी इसी दिशा में चल रही है। भाजपा ने हारी हुई सीटों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए नई रणनीति तैयार की है। पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी सभी सीटों को श्रेणियों में बांटा है, ताकि कमजोर क्षेत्रों को मजबूत किया जा सके। पार्टी की नजर ओबीसी वर्ग और अनुसूचित जाति यानी एएससी वोटबैंक पर है, जहां पार्टी को 2017 से कुछ नुकसान हुआ है। भाजपा गैर-प्रमुख एएससी समुदायों पर विशेष ध्यान दे रही है और राजपूत समुदाय के वोट बैंक को साधने की रणनीति भी बना रही है। भाजपा ने अपनी रणनीति और प्रभावी बनाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण शुरू किए हैं, जिसमें मतदाता व्यवहार, स्थानीय मुद्दे और विपक्ष की रणनीति का अध्ययन शामिल है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के दिलित-पिछाड़ गठजोड़ को मजबूत करने और इस पकट को राजनीतिक

हीतो है, तो वह 2027 के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीती थीं, जिसने भाजपा को केवल 33 सीटों पर सीमित कर दिया था। भाजपा अब विपक्ष के इस गठबंधन को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दीं हैं। हालांकि मुख्य मुकामबला भाजपा गठबंधन और सपा गठबंधन के ही बीच में है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। पिछले चुनाव में बसपा का कोटो भी बसपा से खिसका है। लेकिन उसके लिए पूर्व मुख्तमरी मायावती स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि पिछले दो-तीन चुनाव से वह स्वयं अपनी पार्टी को सम्हाल सकने में कामयाब नहीं हो सकीं हैं। बसपा के ज्यादातर बड़े नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या उनको अनुशासन हीनता के कारण पार्टी से निकाला जा चुका है। बसपा के कमजोर होने का लाभ पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला है। पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में दलित वर्ग ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दिया है और यही कारण है कि सपा कांग्रेस गठबंधन को लोकसभा चुनाव में बेहतरीन परिणाम हासिल हुआ था।

जितेन्द्र सिंह पत्रकार

सेना से सेवानिवृत्त जवान और शून्य आरक्षण की पीड़ा, बिहार-झारखंड में राज्य व्यवस्था की विफलता का आईना

देश की सरहदों पर तैनात सैनिक जब सर्दी, गर्मी, वर्षा और गोलियोंबाजी की परवाह किए बिना अपने प्रणों की बाजी लगाते हैं, तो यह केवल उनकी नौकरी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने जीवन-समर्पण होता है। यह त्याग केवल एक सैनिक का नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार का होता है, जो वर्षों तक उसके बिना जीवन जीता है, बच्चों का लालन-पालन करता है और वक्त यह प्रार्थना करता है कि वह सकुशल लौट आए। लेकिन सबसे बड़ा दुःख तब होता है, जब वही सैनिक अपनी सेवा पूरी कर राज्य में लौटना है और पाता है कि उसके लिए न कोई नौकरी है, न कोई पुनर्वास योजना, न कोई सरकारी संवेदना। बिहार और झारखंड जैसे राज्य इस पीड़ा की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आते हैं। भारतीय सेना में इन राज्यों के हजारों युवक हर वर्ष भर्ती होते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जब वे अपने गृह राज्य लौटते हैं, तो राज्य सरकारें उन्हें बेरोजगारी और अपेक्षा की खाई में धकेल देती हैं। उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में राज्य सरकार की नौकरियों के किसी भी समूह कक्षा क, कक्षा ख, कक्षा ग, और कक्षा घ में पूर्व सैनिकों के लिए एक प्रतिशत भी आरक्षण निर्धारित नहीं किया गया है। यह आंकड़ा कोशिश सभापन संख्या नहीं, बल्कि एक गहरा संवेदनहीनता का प्रतीक है। यह उस समाज की चुप्पी है, जो युद्ध के समय तो 'जय जवान' के नारे लगाता है, पश्चात्ति के दिनों में उन्हीं जवानों को चौकीदार, मजदूर या ठेका चालक बनने पर मजबूर देखाते हैं और चुप रहता है। झारखंड और बिहार की गलियों में आज भी अनेक सेवानिवृत्त सैनिक दिहाड़ें खींचते हैं जो किसी ठेकेदार के अधीन दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, या फिर छोटी मोटी दुकान चलाकर गुजारा कर रहे हैं। क्या यह उस राष्ट्र के लिए शोभनीय है, जो अपने सैनिकों को सम्मान का प्रतीक मानता है? देश के कई अन्य राज्यों में विशेषकर पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और कर्नाटक जैसे राज्यों में राज्य सेवाओं में पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था है। ये राज्य न केवल सैनिकों की सेवा भावना को सम्मान देते हैं, बल्कि उन्हें नागरिक



जीवन में भी गरिमा से जीने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे में बिहार और झारखंड की यह उदासीनता एक प्रकार की सामाजिक नाइंसाफी है, जो लगातार बढ़ रही है। सैनिकों के साथ यह व्यवहार केवल एक वर्ग के साथ अन्याय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मा के साथ धोखा है। जब एक जवान अपना पूरा युवा जीवन सेना को देता है, तो वह केवल पेंशन या मेडल की आशा नहीं करता। वह राज्य से यह अपेक्षा करता है कि जब वह लौटेगा, तो उसे समाज में एक सम्मानजनक स्थान मिलेगा। लेकिन विडंबना यह है कि झारखंड और बिहार जैसे राज्य उसके स्वागत में बेरोजगारी, असुरक्षा और ठोकरें प्रस्तुत करते हैं। इस उपेक्षा की जड़ केवल नीति की कमी नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। न तो झारखंड सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए कोई पृथक पुनर्वास आयोग गठित किया है, न ही बिहार में कोई ऐसी कार्ययोजना अस्तित्व में है जो इन वीरों के भविष्य को सुरक्षित कर सके। दोनों ही राज्यों की सरकारें सेना-भर्ती को तो बढ़ावा देती हैं, भर्ती रैलियों का आयोजन भी करती हैं, परंतु जब वही जवान वापस लौटते हैं तो उन्हें अनुपयोगी नागरिक की तरह देखा जाता है। यह भी समझने योग्य है कि सेना में कार्य करने के दौरान सैनिक अनेक प्रकार की तकनीकी, प्रबंधन, नेतृत्व, और आपदा प्रबंधन संबंधी दक्षताओं को सीखते हैं। ये सभी योग्यताएँ नागरिक प्रशासन, पुलिस सेवा, ग्रामीण विकास, आपदा राहत, परिवहन, सुरक्षा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। लेकिन यदि राज्य सरकारें इन कौशल को उपयोग ही नहीं करेगी, तो यह राष्ट्रीय संसाधनों की भी भारी बर्बादी है। झारखंड जैसे राज्य में जहाँ आदिवासी समाज से बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते हैं, वहाँ की सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने इन बच्चों को सेवानिवृत्ति के बाद

एसा मंच दें, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में पुनः सक्रिय भूमिका निभा सके। यह केवल रोजगार का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, गरिमा और राज्य के प्रति प्रतिबद्धता की भी प्रश्न है। अब आवश्यकता इस बात की है कि बिहार और झारखंड की सरकारें नौद से जागें। उन्हें चाहिए कि वे सेना से सेवानिवृत्त जवानों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करें। उनके लिए कौशल विकास और पुनः नियोजन कार्यक्रम चलाएँ, उनके लिए अलग से राज्य स्तरीय पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना करें, और उन्हें पुलिस, सुरक्षा, होम गार्ड, ग्राम रक्षक दल, वन सुरक्षा, और आपदा प्रबंधन जैसे विभागों में तत्काल नियुक्ति दें। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों में सैनिक सम्मान निधि की स्थापना की जाए जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े जवानों के सैनिकों को आपातकालीन सहायता मिल सके। उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के लिए विशेष अनुदान योजनाएँ चलाई जानी चाहिए। यह संपादकीय आलेख केवल आंकड़ों का हवाला नहीं, बल्कि एक पुकार है उन लाखों सैनिकों के लिए जो अब भी अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, जो अब भी राष्ट्र पहले के मूलमंत्र पर जीते हैं, और जो अब भी अपने राज्यों से सम्मान की एक छोटी सी उम्मीद लगाए हैं। यदि राज्य सरकारें इस पुकार को नहीं सुनतीं, तो यह चुप्पी केवल वर्तमान पीढ़ी के साथ नहीं, आने वाली पीढ़ियों के साथ भी अन्याय होगी। सैनिकों को सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि नीति, योजना और क्रियान्वयन से देना होगा। अब समय आ गया है कि बिहार और झारखंड की सरकारें इन वीरों की पीड़ा को समझें और 'शून्य प्रतिशत' की इस असवेदनशीलता को इतिहास में बदल दें।

अमित कुमार

